

## अनुबंध 4 : राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण

राजकोषीय विकेंद्रीकरण में केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को व्यय और राजस्व उत्तरदायित्व अंतरित करना शामिल होता है। विकेंद्रीकरण के स्तर को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अंतरित स्वायत्तता की सीमा से मापा जा सकता है। स्थानांतरण के स्तर, व्यय का समनुदेशन तथा राजस्व व्यवस्था को देश के संदर्भ में तैयार करना चाहिए जो आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक घटकों पर निर्भर करता है। तथापि, अंततः प्रत्येक देश को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रणाली अपनाने की आवश्यकता होती है।

पिछले कुछ दशकों में व्यय के हस्तांतरण और कुछ हद तक राज्य सरकार के स्तर पर राजस्व बढ़ाने के उत्तरदायित्व की ओर एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति उभरी है यह भी धारणा रही है कि व्यय उत्तरदायित्वों के विकेंद्रीकरण से दक्षता और कल्याण में बेहतर आती है। आर्थिक साहित्य में लंबे समय तक टीबाट (1961), मस्रोव (1969) तथा ओट्स (1972) तथापि साहित्य में यह भी आम धारणा रही है कि विकेंद्रीकरण किए जाने से वितरण संबंधी ईक्विटी और व्यष्टि आर्थिक प्रबंधन में लागत बढ़ सकती है।

### क 4.1 राजकोषीय संघ की प्रमुख विशेषताएं :

अंतर सरकार राजकोषीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के डिजाइन में बहुस्तरीय सरकार व्यवस्था में व्यय का समनुदेशन, राजस्व का समनुदेशन, अंतर सरकार अंतरण, कर लगाना, बजट तैयार करना और वित्तीय प्रबंधन तथा राज्य सरकार के उधारों का नियंत्रण सम्मिलित रहा है।

नियमों के अनुसार यह व्यापक अवधारणा रही है कि व्यय उत्तरदायित्वों के विकेंद्रीकरण से अत्यधिक कल्याणकारी लाभ हो सकते हैं। इस विचार के अनुसार, सरकार के स्तर पर सरकारी व्यय के प्रत्येक स्वरूप के लिए उत्तरदायित्व सौंपने से संसाधनों के आबंटन की दक्षता सर्वोत्तम होती है क्योंकि सरकार के स्तर का प्रत्येक सरकारी व्यय इस परिव्यय के लाभार्थियों से निकटता दर्शाता है। यूरोपियन यूनियन द्वारा अपनाई गई और अधिक परिचालनगत दृष्टिकोण उत्तरदायित्व समनुदेशन के लिए अनुषंगी सिद्धांत का रहा है जिसके अनुसार कराधान, व्यय और विनियामक कार्य सरकार के निचले स्तर द्वारा तब तक प्रयोग किए जाने चाहिए जब तक उन्हें उच्चतर स्तरों तक करने के लिए कोई प्रभावित न करता हो।

सामान्यतया ऐसा माना गया है कि, वितरण तथा विशेष रूप से व्यष्टि आर्थिक प्रबंधन विचारधारा, उन दोनों का विरोध व्यवस्था से होता रहा है। इसके फलस्वरूप राज्य सरकारों को कराधान संबंधी सभी अथवा अधिकांश शक्तियों की ऊपरिगामी राजस्व हिस्सेदारी सौंपी जाती है। ऐसी व्यवस्था होने से व्यष्टि आर्थिक प्रबंधन के लिए कर लिखतों से केंद्र सरकार वंचित रह जाती है। वह व्यवस्था जो केंद्र सरकार को सभी अथवा अधिकांश कराधान शक्तियाँ सौंपती है, अवांछनीय है। राजस्व इकट्ठा करने वाले दायित्वों से व्यय करने वाले प्राधिकरण को अलग कर देने से इस व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक के व्यय और उनके मूल्य के लाभों वाले लिंक स्थापित होते हैं यथा वित्तपोषण हेतु लगाए गए कर। इस प्रकार वे राज्य की राजनीति और उनके चुनावी क्षेत्रों के में राजकोषीय उत्तरदायित्वों का उन्नयन नहीं करते। अतः नियम के अनुसार प्राप्त विकल्प जिसे विश्व भर के देशों में अपनाया गया है। यह ऐसी स्थिति रही है जो सरकार के प्रत्येक स्तर पर राजस्व के अपने संसाधनों का अंतर सरकार अंतरणों के विभिन्न मिश्रणों के साथ समनुदेशन उपलब्ध कराती है ताकि राजस्व और व्यय समनुदेशनों के बीच के अंतराल को भरा जा सके। फिर भी, देशों के बीच राजस्व समनुदेशनों और अंतर सरकार अंतरणों के कारण व्यापक भिन्नता भी रही है।

कुछ देश सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए कर आधारों के पूर्णतः अलगाव के सिद्धांत को मानते हैं। अन्य, उसी कर आधार विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करते हैं। कर पृथक्करण के उदाहरण, अन्य देशों के साथ-साथ भारत, आस्ट्रेलिया और गैर साझी कर जर्मनी में पाए जाते हैं। इसके विपरीत अमरीका और कनाडा में कर अतिव्यापन का पर्याप्त स्तर है।

चूँकि अधिकांश प्रमुख कर विशेष रूप से केंद्र सरकार को समनुदेशित होते हैं, जबकि क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों के पास अत्यधिक व्यय का भार होता है, अतः राज्य सरकार के स्तर पर समांतर असंतुलन अकसर (अर्थात् अंतरण से पहले राजकोषीय घाटे) उभरते रहते हैं। समस्तरीय असंतुलन भी नजर आते हैं क्योंकि अपने राजस्व बढ़ाने की क्षमता अपने-अपने क्षेत्राधिकार में भिन्न होती है। इन असंतुलनों को अंतर सरकारी अंतरणों अथवा घाटे वाले क्षेत्राधिकारों से उधार अथवा दोनों के मिश्रण से कम करना चाहिए। अंतर सरकार अंतरणों की उचित प्रक्रिया राज्य क्षेत्राधिकारों के बीच संसाधनों का वांछित वितरण उन्नयन के लिए निर्णायक होता है। अंतर सरकार अंतरण प्रबंधन को मुख्यतया दो श्रेणियों में बांटा जाता है, राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था और अनुदान अर्थात् सामान्य प्रयोजन अनुदान और विशिष्ट प्रयोजन अनुदान।

तथापि, कुछ संदेह इस बात का होता है कि राजस्व बढ़ाने में पर्याप्त हस्तांतरण और व्यय उत्तरदायित्वों से कराधान और सरकारी व्यय व्यवस्था के लिए नई चुनौतियाँ सामने नजर आती हैं।

#### अनुबंध 4 : राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण (जारी)

केंद्रीकृत प्रशासन के कुछ लाभ हैं, मुख्यतः प्रक्रियाओं की एकरूपता, जिससे पूरे देश में करदाताओं से एकसमान व्यवहार होगा और अनुपालन लागत कम होगी तथा स्तरीय उत्तरदायित्व होगा। दूसरी ओर, विकेंद्रीकृत प्रशासन राज्य प्राधिकरण उन्हें सौंपे गए करों के निष्पादन के लिए अधिक उत्तरदायी और जिम्मेदार होंगे, इसके साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों की प्रणाली और प्रक्रियाएं अपना अधिक सुविधाजनक होगा। विकेंद्रीकृत प्रशासन स्थानीय करों, यथा संपत्ति कर, कारोबार लाइसेंस शुल्क, प्रयोगकर्ता का शुल्क और अन्य छोटी वसूलियों पर अधिक प्रभावी हो सकेगा। राज्य स्तरीय करों का विकेंद्रीकृत प्रशासन, यथा व्यक्तिगत अथवा कंपनी आय कर, अथवा सामान्य कर प्रभावी रूप से लगाए जाने के लिए राज्य प्रशासनों के बीच संबंधित जानकारी के प्रणालीगत विनिमय की आवश्यकता होगी।

सरकार के विभिन्न स्तरों द्वारा सरकारी व्यय प्रबंधन के लिए व्यय उत्तरदायित्वों का पर्याप्त विकेंद्रीकरण भी नई चुनौतियां लायेगा। इन चुनौतियों से केंद्र तथा राज्य सरकारों की बजट संबंधी नीतियों के समायोजन की आवश्यकता बनी रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके राष्ट्रीय व्यष्टि आर्थिक उद्देश्यों के साथ उनकी बारंबारता है। साथ ही, सरकार के सभी स्तरों में प्रत्युत्तर उत्पन्न करने की आवश्यकता बनी रहेगी ताकि बजट संसाधनों तथा वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी के दोनों घटकों के साथ उनकी वरीयता सुनिश्चित की जा सके तथा इससे सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी जुड़ी रहेगी।

राजकीय उधारों के नियंत्रण के अनुभव से देश की समीक्षा किए जाने पर दृष्टिकोणों में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। अन्य बातों के साथ-साथ इनसे राज्य सरकारों की कानूनी और संविधान का स्तर, उन पर केंद्र सरकार के राजनैतिक और प्रशासनिक नियंत्रण का स्तर, वित्तीय अनुशासन में देश की समग्र परंपरा, गंभीर राजकोषीय तथा व्यष्टि आर्थिक असंतुलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति तथा देश के वित्तीय बाजार के विकास की स्थिति स्पष्ट होती है।

राजकीय उधार के नियंत्रण की ओर जाते हुए देश को चार प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता है, हालांकि अधिकांश देश उनका उपयोग मिश्रण के रूप में करते हैं। चार 'पध्दतिबध्द' श्रेणियां हैं : i) बाजार अनुशासन पर एकमात्र अथवा प्राथमिक निर्भरता; ii) डिजाइन में सरकार के विभिन्न स्तरों द्वारा सहयोग तथा ऋण नियंत्रणों का कार्यान्वयन; iii) नियम आधारित नियंत्रण; तथा iv) प्रशासनिक नियंत्रण हैं।

अंतर सरकारी राजकोषीय संबंधों का डिजाइन मुख्य रूप से गैर आर्थिक (राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों के साथ-साथ आर्थिक विचारों से प्रभावित होता रहा है। संकीर्ण आर्थिक संदर्भ में, इन व्यवस्थाओं का डिजाइन विभिन्न उद्देश्यों (जो हमेशा आसानी से समायोजन योग्य नहीं होते) के बीच संतुलन दर्शाता है जैसे : निर्धारित की गई दक्षता, आय का पुनर्वितरण तथा व्यष्टि आर्थिक प्रबंधन।

#### क 4.2 राजकोषीय संघवाद के मुख्य सिद्धांत

किसी देश के लिए उचित हस्तांतरण का स्तर जो भी हो, केंद्र तथा स्थानीय सरकारों और बजट के लिए व्यवस्था के बीच संबंधों को शासित करने वाला कानूनी ढांचा स्पष्ट और कार्यक्षम होना चाहिए। हालांकि सभी स्थितियों के लिए कूटबद्ध कानून अथवा संविदा उपलब्ध कराना असंभव हो जाता है। अतः सुचारु अंतर सरकार राजकोषीय संबंध सुनिश्चित करने के लिए विवाद समाधान तंत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे तंत्र विशेषीकृत निकायों के माध्यम से परिचालन में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए आस्ट्रेलिया, भारत और श्रीलंका में केंद्र सरकार और सरकार के अन्य स्तरों के बीच वित्तीय संबंधों पर कार्रवाई वित्त आयोग करता है।

राष्ट्रीय एवं राजकीय व्यवहार की पारदर्शिता और क्षमता के लिए निम्नलिखित सिद्धांत आवश्यक हैं :

- सरकार के प्रत्येक स्तर का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से समनुदेशित किए जाने चाहिए, चाहे सरकार को समग्र रूप से जो भी उत्तरदायित्व समनुदेशित किए गए हों। सामान्यतया अतिव्यापन से बचना चाहिए तथा हिस्सेदारी उत्तरदायित्वों की लंबी समवर्ती सूचियाँ खासकर अस्पष्ट हो जाती हैं।
- केंद्र तथा स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व हिस्सेदारी वाली व्यवस्था स्थिर होनी चाहिए।
- राज्य सरकारों के पास अपना बजट तैयार करने से पहले इन संसाधनों का सुदृढ़ अनुमान होने की आवश्यकता है। पूर्वानुमान की कमी से दक्षता और राजकोषीय नियंत्रण दोनों स्थानीय स्तर पर प्रभावित होते हैं। राज्य सरकारें संसाधनों की राशि का उल्लेख न होने पर अपने व्यय की रूपरेखा नहीं बना सकती।
- बढ़ी हुई दक्षता के लिए प्रोत्साहन आवश्यक होते हैं। तथापि केंद्र सरकारें अकसर उप राष्ट्रीय सरकारों को अंतरण उस स्थिति में कम करती हैं जब वे अर्थव्यवस्था के उनके अपने कर संग्रहण में व्यय अथवा सुधार बनाती हैं।

## अनुबंध 4 : राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण (जारी)

- व्यय समनुदेशन तथा राजस्व व्यवस्था (कर हिस्सेदारी, अनुदान इत्यादि) दोनों को शामिल करते हुए केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच बहु वर्षीय संविदाओं पर सहमत होना वांछनीय हो सकता है। यदि उचित हो तो इन संविदाओं में निष्पादन मानदंड, स्थानीय सरकार द्वारा दी गई सेवाओं के न्यूनतम मानक इत्यादि शामिल कर सकते हैं। वे पारदर्शी रूप से इन संबंधों को पारिभाषित करेंगे तथा पूर्वानुमान सुनिश्चित करेंगे। अन्य किसी संविदा के समान ही इस व्यवस्था की उपयोगिता इस बात पर निर्भर होगी कि उसकी निगरानी कितनी अच्छी तरह की जाती है।
- राष्ट्रीय नियम में राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और बजट तैयार करने के लिए मानक उपलब्ध होने चाहिए।

### क 4.3 बड़े देशों में राजकोषीय संघ

इस खंड में आस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील और अमरीका जैसे कुछ बड़े संघों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है।

#### क 4.3.1 आस्ट्रेलिया में राजकोषीय संघ

आस्ट्रेलिया में वर्तमान में 6 राज्य, 2 प्रदेश और लगभग 774 स्थानीय सरकारें हैं। कराधान में राष्ट्रीय सरकार का एकाधिकार आस्ट्रेलियाई राजकोषीय प्रणाली की एक विशेषता रही है। वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तियों और व्यवसाय पर आय कर, बिक्री कर, उत्पाद कर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कर कॉमनवेल्थ कर हैं। राज्य सरकारों के मुख्य कर वेतन, वित्तीय और पूंजी लनेदेनों, जुआ, बीमा और मोटर वाहन पर है। स्थानीय सरकारें अचल संपत्ति पर कर लगाती हैं।

1998 में कॉमनवेल्थ ने सभी सरकारी क्षेत्र चालू राजस्व का 68 प्रतिशत, राज्यों ने 28 प्रतिशत और स्थानीय सरकारों ने 4 प्रतिशत एकत्र किया। उसी वर्ष में कॉमनवेल्थ का सीधा व्यय कुल राष्ट्र की तुलना में 51% रहा था, उसके बाद राज्य सरकारों (45 प्रतिशत) और स्थानीय सरकारों का (4 प्रतिशत) का क्रम रहा। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि क्यों आस्ट्रेलिया में राज्य सरकार का अंतर सरकारी अंतरण एक तरफा रहे। इसके कॉमनवेल्थ अनुदान आयोग ने एकसमान व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है। आस्ट्रेलियाई अंतर सरकार राजकोषीय अंतरण प्रणाली समस्तरीय राजकोषीय असंतुलन और असमस्तरीय राजकोषीय असंतुलों के बीच विशिष्ट अनुदान विशिष्ट प्रयोजन भुगतानों और संघ सरकार से राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों को ब्लॉक अनुदान के संबंध में कार्यवाई करती है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव से स्पष्ट है कि आस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कई बड़े देशों में वैट राजस्व का एक बड़ा साधन रहा है। यह राजस्व का दक्ष और उछाल लाने वाला साधन है बशर्ते उसे उचित तरीके से तैयार उसके लगाया जाए। आस्ट्रेलिया में संघीय वैट पूरे देश पर लगाया गया है जिसे राज्यों में बराबरी के अनुदान के रूप में लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था बहुत ही सरल है तथा राज्य सरकार वैट को तैयार करने और लागू करने में आने वाली अनेक जटिलताओं को समाप्त करती है, जैसे कर दरों का सामंजस्य करना। आस्ट्रेलियाई कर सुधार 2000 के भाग के रूप में संघ सरकार ने वैट पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगाया है। आस्ट्रेलिया में संघ सरकार ने आय पर कर लगाने की अलग-अलग शक्ति दे रखी है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि कर प्रणाली में कर दरों और कर आधार में एकरूपता का उच्चतर स्तर है। तथापि, आस्ट्रेलिया में उच्च अंतरण निर्भरता अनुपात से राजकोषीय अपव्ययिता नहीं हुई है क्योंकि सरकार के सभी स्तरों पर राजकोषीय अनुशासन बनाने की आवश्यकता पर मतैक्य रहा है। आस्ट्रेलिया ने विषमस्तरीय असंतुलों को समाप्त करके तथा राज्य सरकारों के बीच समस्तरीय राजकोषीय विषमताओं को कम किया है। आस्ट्रेलिया ने भी राजकीय सेवा स्तरों में पर्याप्त स्तर की समरूपता प्राप्त कर ली है और यह स्पष्ट है कि अंतरण निर्भरता और समकारीकरण से राजकोषीय अपव्ययिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह पूरी तरह तैयार की गई अंतरण प्रणाली है।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और लंदन ने घाटे और ऋण स्तर के लिए नियमों और उद्देश्यों के साथ पारदर्शिता बनाए रखना कानूनी रूप से आवश्यक कर दिया है। आस्ट्रेलिया में नए ढाँचे से 1992-93 में जीडीपी 4 प्रतिशत के घाटे से कम होकर 1999-2000 में 2 प्रतिशत अधिक हो गई। इसके अतिरिक्त, आस्ट्रेलिया में नई रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप पारदर्शिता में सुधार हुआ है, परंतु राज्यों में ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे घाटे पर रोक लगाई जा सके। तथापि, यहां व्यापक सामंजस्य रहा है कि राज्यों को राजकोषीय संतुलन बनाये रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था से राज्यों को लचीलापन मिलता है जिससे कठिन समय में घाटा कम किया जा सकता है। 1980 के दौरान आस्ट्रेलिया ने राज्य सरकारों पर पूंजी बाजारों का मूल्यांकन करने पर रोक लगा दी गई थी और सभी ऋणों को आस्ट्रेलियाई कॉमनवेल्थ ऋण परिषद के माध्यम से केंद्रीकृत कर दिया गया था। ऋण परिषद 1993 में दुबारा गठित किया गया और अब राज्य और अधिक लचीलेपन से परिचालन करते रहे हैं। सुधार के एक भाग के रूप में राज्यों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग की बारंबारता और खुलेपन में सुधार लाएं जो न केवल उनकी वित्तीय गतिविधियों की निगरानी

#### अनुबंध 4 : राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण (जारी)

करता है बल्कि वित्तीय बाजारों को और अधिक विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराता है। कई राज्यों ने पिछले दशक में सामान्य सरकार निवल ऋण के अपने स्तर में अत्यधिक कटौती की है।

##### क 4.3.2 कनाडा में राजकोषीय संघ

कनाडा संघ में 10 राज्यों और 3 संघशासित क्षेत्रों के अतिरिक्त 5600 नगर निगम क्षेत्र हैं जिन्हें 1867 के संविधान से मूल शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्राप्त हुए हैं। राज्यों का प्राधिकार सीमा शुल्क और उत्पाद को छोड़कर शेष सभी करों पर होता है, इन दोनों शुल्कों पर संघ सरकार का पूरा प्राधिकार होता है। व्यावहारिक रूप से, इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों स्तर एक ही प्रकार के करों पर विश्वास करते हैं, इनमें अधिक महत्वपूर्ण हैं व्यक्तिगत और कंपनी आयकर और उपभोग कर। प्राकृतिक संसाधनों पर औपचारिक रूप से राज्यों का अधिकार है केवल राज्य और स्थानीय सरकारों की कर संपत्ति और जुआ राजस्व तथा इनकी निर्भरता भिन्न-भिन्न प्रकार की उपयोगकर्ता शुल्क और प्रभारों पर है।

हालांकि राज्यों को अपने कर आधार और दरों को पारिभाषित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है परंतु व्यावहारिक रूप में अधिकांश राज्यों के आय कर संघ सरकार द्वारा इस शर्त पर एकत्र किए जाते हैं कि संघ आधार और राज्य का आधार एकसमान रहेगा। कनाडा में संघ और राज्य सरकारों के बीच कर संग्रहण समझौता इसी आय कर के आधार पर किया जाता है। क्यूबेक और ओन्टारियो अपवादात्मक राज्य हैं जो अपने व्यक्तिगत और कंपनी आय कर केंद्र द्वारा प्रभारित दर के अनुपात में स्वयं निर्धारित करते हैं। कनाडा में संघीय वैट है जो पूरे देश पर लागू होता है। ब्राजील के विपरीत कनाडा के राज्यों में विभिन्न उपभोग कर लगाए जाते हैं। 1997 से तीन राज्यों ने अपने बिक्री करों का समेकन संघ के मूल्य संवर्धन कर के साथ (कनाडा के वस्तु और सेवा कर के संदर्भ में) समस्तरीय बिक्री कर के साथ कर लिया गया है, जो संघ सरकार द्वारा लिया जाता है। राज्य उधार लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें संघ सरकार द्वारा समीक्षा अथवा नियंत्रण नहीं होता। क्यूबेक द्वारा लगाया जाने वाला वैट एकसमान दर पर लगाया जाता है। अल्बर्टा में व्यापक आधार उपभोग कर नहीं लगाया जाता तथा शेष पांच राज्य फुटकर बिक्री कर (आरएसटी) का कुछ भाग लगाते हैं। ब्राजील के समान कनाडा का वैट भी पूर्णतया विश्वसनीय रहा है।

यह तथ्य कि व्यय के हस्तांतरण में सरकार के विभिन्न स्तर सम्मिलित होते रहे हैं, अतः अंतर सरकार सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि विकेंद्रीकरण सुधारों का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। जर्मनी के “सहयोग संघ वाद” में बहु स्तरीय समितियों के व्यापक नेट के माध्यम से सभी निर्णय लिए जाते हैं जबकि आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में चुने हुए पदाधिकारियों और अधिकारियों की आवधिक बैठकें आपस में मुख्य राजकोषीय मुद्दों पर चर्चा हेतु की जाती हैं। कनाडा में, राजकोषीय व्यय नियंत्रण अधिनियम 1992 में एक मामूली व्यय सीमा निर्धारित की गई थी तथा इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी व्यय वृद्धि को कम करना, राजकोषीय असंतुलनों को कम करना तथा जनता के ऋण में वृद्धि को रोकना था। वर्ष 1995 में जीडीपी में रहा 5 प्रतिशत घटा वर्ष 1999 में समाप्त होकर जीडीपी से 1 प्रतिशत अधिक हो गया तथा जीडीपी की तुलना में निवल जनता का ऋण 1995 में 70 प्रतिशत से कम होकर 2000 में 52 प्रतिशत रह गया।

देश के समस्तरीय असंतुलनों का आकार मुख्यतया व्यय और राजस्व समनुदेशनों का कार्य रहा है। कनाडा में समस्तरीय लघुतर अंतराल की वास्तविकता यह है कि कनाडा के राज्यों की पहुँच सभी प्रमुख व्यापक आधार करों तक है तथा सरकार के विभिन्न स्तरों के कतिपय आधारों का प्रयोग संवैधानिक नियमों में नहीं आता है। राज्य अपनी दरें स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। वर्तमान में राज्य अपने राजस्व अपने संसाधनों से बढ़ाते हैं तथा समग्र संघ अंतरण राज्य के कुल राजस्व का केवल 13 प्रतिशत रहा है। तथापि अंतरण निर्भरता उच्च आय वाले राज्यों में 10-12 प्रतिशत से लेकर कम आय वाले राज्यों में लगभग 40 प्रतिशत रहा है।

कनाडा में अंतर सरकारी राजकोषीय अंतरण का प्रमुख लक्ष्य राज्यों की स्थानीय जन सेवाओं में न्यूनतम राष्ट्रीय मानक उपलब्ध कराना है। इनमें से मुख्य दो कनाडा स्वास्थ्य और सामाजिक अंतरण (सीएचएसटी) और समान अंतरण रहा है। बाद का अंतरण समस्तरीय असंतुलनों पर केंद्रित है जबकि सीएचएसटी ऊर्ध्वमुखी राजकोषीय अंतराल को कम करने का प्राथमिक उपाय है।

##### क 4.3.3 ब्राजील में राजकोषीय संघ

ब्राजील अत्यधिक विकेंद्रीकृत संघ है जिसमें 27 राज्य (संघ जिलों सहित) और 5,559 नगरपालिका हैं। 1988 संविधान में ब्राजील में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को और अधिक गहन बना दिया है तथा कर्ज में डूबे राज्यों और नगरपालिकाओं को और अधिक स्वायत्तता दे दी गई है। राज्यों को व्यापक आधार वाला उच्च आय वैट समनुदेशित किया गया जो उन्होंने एकत्र किया और लगाया तथा उन्हें अपना वैट दर निर्धारित करने की

#### अनुबंध 4 : राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण (जारी)

स्वायत्तता दी गई। ब्राजील में सतत विकेंद्रीकरण प्रवृत्ति की विशेषताएं राज्यों की अपेक्षा नगरपालिकाओं पर जोर देना है क्योंकि वे सेवा सुपुर्दगी के प्रमुख एजेंट रहे हैं, विशेष रूप से समाज सेवा और जन निवेश के क्षेत्र में।

हाल ही के सुधारों में अंतर सरकारी राजकोषीय संबंधों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून और अनुपूरक कानून में सरकार के सभी स्तरों पर राजकोषीय ईमानदारी बरतने के लिए काफी प्रोत्साहन दिया गया है। राज्य सरकारों का संघ अंतरण, संघ राजस्व का लगभग 1/5 था तथा राज्य और नगर पालिका का क्रमशः 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत था। 1989 में राज्यों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप राज्यों के समस्तरीय असंतुलनों को सुधारने की वजह से नए सुधारों ने राज्यों के राजकोषीय संबंधों में सुधार लाया है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य भागीदारी निधि का 85 प्रतिशत हिस्सा उत्तर, उत्तर पूर्व और केंद्र पश्चिम के अपेक्षाकृत गरीब राज्यों को अंतरित किया गया जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के समृद्ध राज्यों को राजस्व हिस्से का कम भाग मिला। राज्यों से उनके क्षेत्राधिकार की नगरपालिकाओं को आवश्यक अंतरण तथा सामाजिक सेवाओं के प्रावधान में नगरपालिकाओं पर बढ़ते दबाव के कारण सरकार के कुल व्यय और राजस्व में राज्य का हिस्सा कम हुआ है।

ब्राजील के मामले में कर सुधारों के मुख्य उद्देश्य कर चोरी को कम करना रहा है तथा स्थानीय राजस्व संग्रहण, विशेष रूप से नगरपालिका स्तर पर, को मजबूत बनाना रहा है। स्थानीय राजस्व संग्रहण पर अधिक जोर देने से यह स्पष्ट होता है कि अनुदान पर सरकार के निचले स्तर की निर्भरता कम करने तथा सरकार के उच्चतर स्तर का अंतरण कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमुख राजस्व सुधार वैट लागू करने और राज्यों के अपने संसाधन पर कर राजस्व से संबंधित रहे हैं।

ब्राजील में, संघ वैट औद्योगिक वस्तुओं पर लागू होता है जबकि राज्य वैट सामान्य तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के परिचालन पर कर लगाता है तथा नगर पालिका सेवाओं की विशिष्ट सूची पर प्रभार लगाती है। यह नोट करने योग्य है कि राज्य वैट की तुलना में संघ वैट पूर्णतया विश्वसनीय है। हालांकि ब्राजील के राज्य, राज्य वैट से अपने स्वयं के संसाधन राजस्व का लगभग 85 प्रतिशत प्राप्त करते हैं, विभिन्न राज्यों में विभिन्न वैट को लागू करने के मामलों में कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं बढ़ती हैं। इसके अतिरिक्त इन तीन करों के कर आधार अतिव्यापी होने से अव्यवस्था और अक्षमता भी उत्पन्न होती है।

बार-बार राजकोषीय संकट के इतिहास के बाद ब्राजील ने एफआर एल (2000) अधिनियमित किया है। ब्राजील ने घाटे और ऋण नियमों और व्यय नियमों को झकड़ कर अपने कानूनी उत्तरदायित्व में पारदर्शिता लाई है। ब्राजील के राज्यों का बजट लचीला नहीं है क्योंकि पेंशन, ब्याज और मजदूरी पर किया गया व्यय उनके वर्तमान व्यय दर्शाता है। एफआरएल के अनुसार कार्मिकों पर किया गया व्यय राज्य के निवल वर्तमान राजस्व के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा इसी प्रकार, नगरपालिकाओं के लिए भी यह सीमा 60 प्रतिशत है। कुछ राज्यों ने उक्त व्यय वांछित स्तर तक रखा गया है। ऋण सेवाओं पर व्यय के लिए वर्तमान अधिकतम सीमा राज्य और नगरपालिका राजस्व का 13 प्रतिशत रहा है। निवल ऋण की अधिकतम सीमा स्थानीय सरकारों के निवल राजस्व का 1.2 गुना तथा राज्य सरकारों के लिए निवल राजस्व का दोगुना है। यदि कोई स्थानीय सरकार यह सीमा पार करती है तो उन्हें एक वर्ष के भीतर उस हिस्से से ऊपर के भाग की चुकौती करनी होती है। ब्राजील के एफआरएल में भी बहु वर्षीय बजटों की अपेक्षा होती है जिसमें राजस्व, व्यय और ऋणग्रस्तता के लिए तीन वर्ष के लक्ष्य होते हैं। एफआरएल का एक महत्वपूर्ण घटक केंद्र द्वारा राज्य और स्थानीय सरकारों का भविष्य में होने वाली निकासी की तुलना में निषेध से संबंधित रहा है। कानून के अनुसार यदि ऋण चुकौतियां निवल राजस्व के 13 प्रतिशत से अधिक होती हैं तो राज्य और स्थानीय सरकार के वित्त संतुलित होने चाहिए। इसे लागू होने के चार वर्ष बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एफआरएल ने ब्राजील में राजकोषीय समायोजन किया है जैसा कि घटते हुए ऋण और घाटे अनुपात से परिलक्षित होता है।

ब्राजील में, बढ़ती हुई राजस्व स्वायत्तता और कम होती हुई अंतरण निर्भरता को राज्य सरकारों के बीच और अधिक राजकोषीय अनुशासन के आगे बढ़ने के माध्यम के रूप में देखा गया है। तथापि, कर स्वायत्तता समस्तरीय अंतराल को कम करने के लिए पर्याप्त शर्त नहीं रखी गई है क्योंकि राज्य सरकारों को कठिन बजट बाध्यताओं के अंतर्गत काम करना पड़ता है।

ब्राजील में एक समान अंतरण संसाधनों के बड़े आबंटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें राज्य और नगरपालिका सहभागिता निधि सम्मिलित होती है जो केंद्रीकृत रूप से एकत्र किए गए आय करों और राष्ट्रीय वैट से संग्रह किए जाते हैं, इनमें से क्रमशः 21.5 प्रतिशत और 22.5 प्रतिशत इन निधियों में जाता है। राज्य सहभागिता निधि (तीन बड़े संघ करों के राज्य के हिस्से) प्रत्येक राज्य के लिए सहभागिता गुणांक पर आधारित होता है। सहभागिता गुणांक की गणना करने का फार्मूला एक समान करने अथवा पुनः वितरण के मानदंड पर आधारित होता है। इसके परिणामस्वरूप निधि का 85 प्रतिशत भाग उत्तर, उत्तर पूर्व और पश्चिम में कम आय वाले क्षेत्रों को जाता है।

## अनुबंध 4 : राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण (जारी)

### क. 4.3 4 अमरीका में राजकोषीय संघवाद

अमरीका की संघीय व्यवस्था अति विकेंद्रित है और सामान्यतः सुप्रबंधित संघीय राजकोषीय व्यवस्था का उदाहरण मानी जाती है। वर्तमान में, अमरीका में 50 राज्य, 1 संघीय जिला और 87,528 स्थानीय सरकार हैं। अमरीका का संविधान वे सभी कार्य करने की अनुमति देता है जो स्पष्ट रूप से संघीय सरकार के लिए आरक्षित नहीं हैं और जिससे संविधान का उल्लंघन न होता हो। सरकार के संघीय और राज्य दोनों श्रेणियों में निजी आय पर कर लगाया जाता है, यद्यपि संघीय आय कर राज्यों के लिए बहुत ही कम गुंजाइश छोड़ता है। अधिकांश राज्य निजी आय पर और सामान्यतः बिक्री कर पर निर्भर करते हैं जिनसे उन्हें उनके कर राजस्व का दो तिहाई भाग प्राप्त होता है।

वर्षों में, अमरीका को अधिक विकेंद्रीकरण के प्रति सरकार के प्रत्येक स्तर पर राजस्व और व्यय के योग में बदलाव दिखा है। 2002 में, राज्यों का कुल राजस्व का लगभग 66 प्रतिशत भाग स्वयं के स्रोतों से प्राप्त हुआ, जबकि स्थानीय सरकार ने स्वयं के स्रोतों से कुल राजस्व का 55 प्रतिशत भाग जुटाया। 2002 में संघीय सरकार का व्यय कुल व्यय के 50 प्रतिशत था, जबकि कुल व्यय का शेष आधा भाग राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा व्यय हुआ था।

अति कम राजकोषीय असंतुलन अमरीका की विशेषता है, किंतु राज्य और स्थानीय सरकार उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संघीय सरकार से प्राप्त अंतरणों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं जिसमें उक्त अंतरण राज्यों के कुल राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत होता है। उसी प्रकार, राज्य सरकारें उनके कुल राजस्व के लगभग 37 प्रतिशत के लिए (33 प्रतिशत राज्य से और 4 प्रतिशत संघीय स्तर पर) अंतर-सरकारी अंतरणों पर निर्भर करती हैं। राज्यों के बीच राजकोषीय क्षमता की समता की कोई व्यवस्था न होने पर भी अनुदान कार्यक्रम के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से राजकोषीय समानता बन जाती है।

अमरीका में उप-राष्ट्रीय सरकारें सैद्धांतिक रूप से संघीय सहभागिता के बिना उधार लाने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु हकीकत में, संघीय सरकार राज्य और स्थानीय बाँडों के व्याज को संघीय आय कराधान से छूट देकर उप-राष्ट्रीय उधारों को सहायता प्रदान करती है। अमरीका में केंद्र सरकार ने नो-बेलआउट नीति अपनाई है और लगभग सभी राज्यों में स्वयं का लगाया हुआ संतुलित - बजट नियंत्रण है।

### क 4.3.5 राजकोषीय अनुशासन के लिए संस्थागत ढांचा

राजकोषीय अनुशासन के लिए संस्थागत ढांचा बलेंस ऑपरेटिंग बजट संबंधी प्रभावी नीति, राज्य व्यय प्राधिकारी और दायित्व, राज्य राजस्व-जुटाने के प्राधिकारी, बजटीय पारदर्शिता और नागरिकों की सहभागिता, राष्ट्रीय अंतरण नीति और राज्यों के उधार लेने के प्राधिकार से संबंधित नीतियों जैसे महत्वपूर्ण कुछ संस्थागत कारक सरकार के उप-राष्ट्रीय स्तरों पर अच्छा राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के प्रयोजनार्थ आस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील का राजकोषीय अनुशासन का संस्थागत ढांचा और भारत की स्थिति की तुलना सारणी अनुबंध 4 क में दी गई।

### सारणी अनुबंध 4 क : उप-राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय अनुशासन का संस्थागत ढांचा

क	नीति	ऑस्ट्रेलिया	ब्राजील	कनाडा	भारत
	1	2	3	4	5
<b>क</b>	<b>बैलेंस ऑपरेटिंग बजट्स संबंधी प्रभावी नीतियां</b>				
1.	बैलेंस ऑपरेटिंग बजट्स संबंधी प्रभावी संस्थागत नियम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2.	बैलेंस ऑपरेटिंग बजट्स संबंधी प्रभावी सांविधिक नियम	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
3.	संतुलित बजट नियमों का उल्लंघन करने वाले सरकारी अधिकारियों पर प्रभावी दंड लगाया जाता है।	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
4.	किसी स्वतंत्र 'दीवालिया' न्यायालय या संस्था द्वारा लागू सशर्त बेलआउट कार्यान्वित करने की व्यवस्था प्रचलित है।	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
<b>ख</b>	<b>राज्य व्यय प्राधिकारी और दायित्व</b>				
1.	राज्यों के सेवा दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और राज्य को कार्यों के लिए उनके व्यय के प्रबंधन का अधिकार है।	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2.	राज्यों को अदृश्य बजटीय कठिनाइयों की स्थिति में कार्मिक और वेतन जैसी मुख्य मदों के व्यय कम करने का अधिकार है।	हाँ	नहीं	हाँ	कोई विशेष प्रावधान नहीं
3.	राज्य पेन्शन व्यवस्था के लिए बीमांकन रूप से मजबूत, पूर्णतः निधिकृत (पे-ऑन-यू-गो के स्थान पर) आधार पर कार्य करना आवश्यक है।	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं

**अनुबंध 4 : राजकोषीय संघ वाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण (जारी)**

**सारणी अनुबंध 4 क : उप-राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय अनुशासन का संस्थागत ढांचा**

नीति	आस्ट्रेलिया	ब्राजील	कनाडा	भारत
1	2	3	4	5
<b>ग. राज्य राजस्व जुटाने वाली प्राधिकारी</b>				
1. राज्यों को कर लगाने के पर्याप्त अधिकार हैं (दर निर्धारण का अधिकार) ताकि विशिष्ट राज्य उनके ऑपरेटिंग बजट के कम से कम आधे हिस्से का वित्तपोषण अपने स्वयं के करों से कर सकें।	नहीं	हाँ, बड़े राज्य, छोटे राज्य नहीं	हाँ	हाँ
2. राज्यों के कर लगाने के अधिकार सीमित हैं जिससे भार का पर्याप्त हिस्सा अनिवासियों पर अंतरित करने की अनुमति नहीं मिलती है, सिवाय उस सीमा तक कि अनिवासी राज्य द्वारा दी गई सेवाओं के विशेष रूप से महत्वपूर्ण लाभार्थी के रूप में पहचाना जाता हो।	हाँ	सामान्यतः	(नैसर्गिक संसाधनों के दोहन पर कर)	हाँ
3. राज्य को उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और अन्य करेतर राजस्व संग्रह करने का अधिकार है ताकि वे सार्वजनिक उपयोगिता का पूर्ण-लागत वसूली आधार पर वित्त पोषण कर सकें और सार्वजनिक सेवाओं की लागत (अन्य) के बड़े भाग का वित्त पोषण कर सकें जिसके लिए यह सीधा ही संभव होगा कि लाभार्थी पर प्रभार लगाया जाए।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4. सामान्यतः, राज्य राजस्व जुटाने वाला प्राधिकार पर्याप्त है जिससे अदृश्य बजटीय कठिनाइयों की स्थिति में राज्य अतिरिक्त राजस्व मार्जिन में जुटाने की स्थिति में हो।	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
<b>घ. बजटीय पारदर्शिता और नागरिकों की सहभागिता</b>				
1. राज्य द्वारा दीर्घावधि ऋण के प्रत्येक निर्गम के लिए आधिकारिक सरकारी अनुमोदन से पहले राष्ट्रीय नीति के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई आवश्यक है।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2. राज्य द्वारा दीर्घावधि ऋण के प्रत्येक निर्गम के लिए सार्वजनिक जनमत संग्रह राष्ट्रीय नीति के अनुसार आवश्यक है।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3. राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रस्तावित और वास्तविक राज्य बजट का प्रकाशन (सारांश), बजट अपनाने से पहले सार्वजनिक सुनवाई करना और अपनाए गए बजट का प्रकाशन आवश्यक है।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4. राष्ट्रीय नीति राज्य लेखांकन और बजटांकन के लिए कड़े मानदंड निर्धारित करती है, जिसमें अधिमानतः सभी राजस्व और व्ययों की पूर्ण-उपचय रिपोर्टिंग शामिल है।	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
5. राष्ट्रीय नीति के अनुसार राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरणों की समय पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समय पर प्रकाशन आवश्यक है।	नहीं	नहीं	हाँ	यह सांविधिक है।
6. राष्ट्रीय राजकोषीय दायित्व कानून बनाया गया है।	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
<b>ङ. राष्ट्रीय अंतरण नीति</b>				
1. राष्ट्रीय नीति विवेकपूर्ण अंतरणों पर केंद्र सरकार की निर्भरता को कम करती है।	हाँ	सामान्यतः ऋण राहत को छोड़कर अधिकतर	हाँ	हाँ काफी मात्रा में
2. सामान्य राजकोषीय सहायता के राष्ट्रीय अंतरण सांविधिक सूत्रों (मूल सहायता अर्थात् विभाजित करों सहित) के आधार पर वितरित किए जाते हैं और सूत्रों में अंतर राज्यों की वास्तविक नीतियों से अलग होते हैं।	हाँ		हाँ	हाँ, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और कुछ राज्य आयोजना की योजनाओं को छोड़कर
3. सामान्य राजकोषीय सहायता का काफी हिस्सा सांविधिक सूत्र के आधार पर वितरित किया जाता है जो राज्य राजकोषीय क्षमताओं की प्रणालीगत समानता प्रदान करता है।	हाँ	बहुत मोटे तौर पर	हाँ	हाँ
4. राष्ट्रीय कैटेगरीकल अनुदान कार्यक्रमों के लिए ऐसे पात्र कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए अपने राज्यों के राजस्व से प्रचुर मात्रा में मैचिंग अभिदान की आवश्यकता होती है।	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के एक भाग के रूप में

**अनुबंध 4 : राजकोषीय संघ - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण (समाप्त)**  
**सारणी अनुबंध 4 क : उप-राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय अनुशासन का संस्थागत ढांचा**

नीति	आस्ट्रेलिया	ब्राजील	कनाडा	भारत
1	2	3	4	5
5. राष्ट्रीय नीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अधिदेशाधीन खर्चों की यथोचित प्रतिपूर्ति की जाती है।	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
6. राष्ट्रीय नीतियां कई वर्षों तक केन्द्र के भविष्य में अंतरण के प्रवाहों के अनुमान के जरिए तथा अंतरण प्रवाह की अनपेक्षित घटबढ़ को काफी हद तक कम करके बहुवर्षीय राज्य बजट आयोजना को सुगम बनाती है।	हाँ	नहीं	हाँ	काफी हद तक
<b>च उधार लेने के राज्यों के प्राधिकार से संबंधित नीतियां</b>				
1. राष्ट्रीय नीति नकदी प्रवाह प्रयोजनों के अलावा अन्य राज्य उधारियों की अनुमति नहीं देती।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2. राष्ट्रीय नीति में केंद्र सरकार की किसी संस्था (ओं) द्वारा जारी राज्य बांड निर्गमों के लिए अग्रिम अनुमोदन आवश्यक है।	हाँ	हाँ, लेकिन खामियां हैं	नहीं	हाँ, जब केन्द्र सरकार का ऋण बकाया हो
3. राष्ट्रीय नीति में समाप्त से पहले राज्य बांड निर्गमों का केन्द्र सरकार की किसी संस्था में पंजीकरण या ब्योरों की रिपोर्टिंग आवश्यक है।	हाँ	सामान्यतः	नहीं	नहीं
4. राष्ट्रीय नीति में राज्यों को विदेशी ऋणदाताओं से उधार लेने की अनुमति नहीं है।	हाँ	नहीं, लेकिन गारंटी वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।	नहीं	हाँ, सांविधिक रूप से
5. किसी राज्य का किसी एक समय यदि बकाया रहा हों तो राष्ट्रीय नीति बकाया दीर्घावधि ऋण के मूलधन पर सीलिंग लगाती है।	बातचित से तय वार्षिक सीमा	हाँ, सिनेट द्वारा राजकोषीय जवाबदेही कानून	नहीं	नहीं
6. राष्ट्रीय नीति ऐसे किसी भी निहितार्थ का भरोसा नहीं दिलाती है कि किसी बांड का निर्गम जारीकर्ता राज्य के पूर्ण विश्वास और विश्वास से हर तरह से सुरक्षित है।	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
7. राष्ट्रीय नीति राज्यों को उनके बकाया ऋण पर चूक के जोखिम	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं

\* बांड निर्गमों के संदर्भों में राज्य-प्रायोजित उद्यमों और अन्य ऐसी संस्थाओं द्वारा जारी ऋण लिखतों की गारंटी के लिए राज्य के करारों को शामिल माना जाए।  
 उ.न. : उपलब्ध नहीं

**टिप्पणी :** बाद में हुए परिवर्तनों को इस सारणी में शामिल नहीं किया है।

**स्रोत :** रफ्यूज, रोबर्टी, ज्यूनीयर मार्क गेल्माघर एवं स्टीव रॉजनेर (2003); "संघ-निर्मित देशों में उप-राष्ट्रीय राजकोषीय सुधारों के अनुभवों पर गोलमेज के लिए तैयार किया गया पृष्ठभूमि पर्चा", आगरा, भारत, दिसंबर 6-7.

**संदर्भ :**

1. बहल रॉय, यूनिस् हेरेडिया - आर्टीज, जॉर्ज मॅट्टिनेज -वाजक्वेज एंड मार्क राइडर (2005): "फिस्कल कंडीशन ऑफ स्टेट्स, इंटरनैशनल एक्सपीरियंस एंड ऑप्शंस फॉर रिफॉर्म"।
2. इकॉनोमिक सर्वे ऑफ आस्ट्रेलिया, 2005
3. युस्त्राव, आर., 1969 "थ्योरीज ऑफ फिस्कल फेडरलीजम." पब्लिक फाइनेंस, वॉल्युम 24 नं.4, पीपी.521-32.
4. ओट्स, वालेस ई., 1972, फिस्कल फेडरलीजम (न्यूयार्क : हारकोर्ट ब्रेस जोवेनोविच)
5. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनोमिक को. ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट (2003), इकॉनोमिक आउटलुक।
6. रफ्यूज, डब्ल्यू राबर्टो, ज्यू. मार्क गेल्माघर, एंड स्टीव रॉजनेर (2003): "बैंकग्रांड पेपर प्रिपेयर्ड फॉर राउंडटेबल ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सब-नैशनल फिस्कल रिफॉर्म इन फेडरली स्ट्रक्चर्ड कंट्रीज." आगरा, इंडिया, दिसंबर 6-7.
7. रोबर्टो, नोज. आर अफोसो एंड लुइस डीमेलो (200): "ब्राजिल : एन इवोल्विंग फेडरेशन." इंटरनैशनल मॉनिटरी फंड।
8. सल्वाटोर शेवो-कैम्पो एंड पचमपेट सुंदरम, 2000 "टू सर्व एंड टू प्रिजर्व: इंप्रूविंग पब्लिक एंडमिनिस्ट्रेशन इन ए कंपैटेटिव वर्ल्ड." एडीबी।
9. सुदरलैंड, डगल्स एंड इसाबेला जोमार्ड (2006): "फिस्कल रूल फॉर सब-सेंट्रल गवर्नमेंट्स, डिजाइन एंड इंपेक्ट". ओइसीडी।
10. टेर-मिनासियन, टेरेसा, 1997. "फिस्कल फेडरलीजम इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस" 3डी. आईएमएफ।
11. - 2006. "फिस्कल एडजस्टमेंट फॉर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ"। इंटरनैशनल मॉनिटरी फंड।
12. टिबाउट, सीएम.1961, एन इकॉनोमिक थ्योरी ऑफ फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन इन पब्लिक फाइनेंस : नीड्स, सोर्सेस एंड युटिलाइजेशन (प्रिंसटोन, न्यू जर्सी : प्रिंसटोन युनिवर्सिटी प्रेस)